दिनांक: 03.09.2024

सं.एपीडा-एसएसटीबी/4/2024-डब्ल्यूटीओ

कृषि उत्पादों पर डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों से एसपीएस और टीबीटी अधिसूचनाओं को संभालने में एपीडा और ईआईसी की सुगमता के लिए फर्मों/एजेंसियों (अधिमानतः कानूनी फर्मों) से बोलियां आमंत्रित करना

1. परिचय:

1.1 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) वाणिज्य विभाग (डीओसी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संगठन हैं। एपीडा को भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ईआईसी को भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के प्रमाणन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.2 एपीडा कृषि व्यापार को सुगम बनाने तथा निर्यात स्थलों का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि एवं खाद्य उत्पादों की बाजार पहुंच को सुगम बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। ईआईसी भारत का एक प्रमाणन निकाय है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके लिए सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी (एसपीएस), व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के मुद्दों को संबोधित करने की भी आवश्यकता है, जो बाजार पहुंच की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

1.3 गतिशील एसपीएस टीबीटी व्यवस्था के तहत आयातक देशों की आवश्यकताओं के निरंतर अनुपालन के लिए उनकी विनियामक व्यवस्था की निरंतर निगरानी की आवश्यकता है और अतिरिक्त आवश्यकताओं/अनुपालनों के रूप में परिवर्तनों के आधार पर , उनसे निपटने के लिए एक उपयुक्त कार्य योजना का विकास करना होगा ताकि उन वस्तुओं के हमारे निर्यात पर कोई/न्यूनतम प्रभाव न पड़े।

1.4 इन मुद्दों को संयुक्त रूप से संबोधित करने में दक्षता बढ़ाने के लिए , एपीडा और ईआईसी, कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा एसपीएस/टीबीटी

अधिसूचनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए सलाहकार के रूप में एक फर्म/एजेंसी की नियुक्ति करने हेतु इच्छुक है और एपीडा और ईआईसी को उचित रूप से सलाह देने हेतु भी इच्छुक है।

2. असाइनमेंट के बारे में

डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों से एसपीएस और टीबीटी अधिसूचनाओं से डील करने में एपीडा और ईआईसी को सुगम बनाने के लिए फर्मों/एजेंसियों (अधिमानतः कानूनी फर्मों) से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

3. बोलियां प्रस्तुत करने की पात्रता

3.1 इच्छुक फर्म/एजेंसियां (अधिमानतः कानूनी फर्म) , जो पिछले पांच वित्तीय वर्षों या उससे अधिक समय से विद्यमान में हैं, और निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करती हैं , समान प्लेटफार्म पर समान कार्य के निष्पादन में वांछित अनुभव और विशेषज्ञता रखती हैं , बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

3.2 आवेदक एजेंसी को विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों , एसपीएस और टीबीटी उपायों , अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत के निर्यात , विदेशी व्यापार आदि पर इसके प्रभावों से उचित रूप से परिचित होना होगा।

4. कार्य-क्षेत्र

4.1 फर्म/एजेंसी निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करेगी:

(i) डब्ल्यूटीओ वेबसाइट से दैनिक आधार पर सभी एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं को डाउनलोड करना, भारत के लिए प्रासंगिक एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं को वर्गीकृत और चिह्नित करना , और प्रासंगिक अधिसूचना के गैर-कानूनी सारांश के साथ प्रासंगिक अधिसूचना को संबंधित हितधारकों को अग्रेषित करना। (हितधारकों की प्रति एपीडा/ईआईसी/डीओसी द्वारा साझा की जाएगी)। यदि प्रासंगिक अधिसूचना अंग्रेजी भाषा में नहीं है , तो एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध संसाधनों से अंग्रेजी अनुवाद करे और संबंधित हितधारकों के साथ साझा करे;

(ii) एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं को क्षेत्रवार अलग करना (ताजे फल और सब्जियां , पशु मूल के उत्पाद , अनाज, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ , समुद्री उत्पाद , फार्मास्यूटिकल्स, रसायन आदि);

(iii) कारकों के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं को वर्गीकृत और चिह्नित करना जैसे (क) कम से कम पिछले पांच वर्षों के लिए अधिसूचित देश से/को संबंधित उत्पाद के संबंध में भारत [1] का निर्यात/आयात डेटा, (ख) कम से कम पिछले पांच वर्षों के लिए संबंधित उत्पाद के लिए उक्त अधिसूचित देश का आयात/निर्यात डेटा[2], (ग) कोई अन्य पैरामीटर जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है;

(iv) अधिसूचित विनियमन का गैर-कानूनी सारांश तैयार करना;

(v) उपर्युक्त सारांश को मासिक कोर समिति की बैठकों से पहले मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में इनपुट/टिप्पणियों के लिए प्रसारित किया जाएगा। प्राप्त इनपुट को एकत्रित करके सारांश ("सारांश") में शामिल किया जाना अपेक्षित है;

(vi) सभी एसपीएस और टीबीटी अधिसूचनाओं की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करें और हर सोमवार को वाणिज्य विभाग (डीओसी)/एपीडा/ईआईसी को प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हो:

- अधिसूचना से प्रभावित होने वाले उत्पाद तथा छह अंकों का एचएस कोड।
- अधिसूचना में आधिकारिक दस्तावेजों का सारांश जिसमें स्पष्ट रूप से सामग्री का आकलन किया गया हो
- अधिसूचना का भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव तथा
- प्रभावित होने वाले हितधारकों की सूची
- जिम्मेदार एजेंसियों के संकेत के साथ प्रस्तावित कार्रवाई

(vii) आपातकालीन अधिसूचनाओं या शीर्ष प्राथमिकता-प्राप्त अधिसूचनाओं के मामले में , उपरोक्त सारांश और प्रस्तावित कार्रवाई के साथ डीओसी/एपीडा/ईआईसी और संबंधित हितधारकों को तुरंत सूचित किया जाएगा;

---

[1] भारत से संबंधित निर्यात/आयात डेटा भारत सरकार के स्रोत जैसे डीजीसीआईएस, डीओसी आदि से एकत्र किया जाएगा।

[2] अधिसूचित देश से संबंधित निर्यात/आयात डेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्रोतों जैसे आईटीसी व्यापार मानचित्र, यूएन कॉमट्रेड या संबंधित देश की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से एकत्र किया जाएगा।

(viii) चिह्नित एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं को विश्लेषण सहित सभी घरेलू हितधारकों , जिनमें संबंधित मंत्रालय/विभाग, डीओसी के प्रादेशिक और कमोडिटी प्रभाग , कमोडिटी बोर्ड (कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, तंबाकू बोर्ड आदि), निर्यात संवर्धन परिषद, और उद्योग निकाय/एसोसिएशन या कोई अन्य प्रासंगिक संगठन शामिल हैं , को प्रसारित करना तथा उनकी टिप्पणियां प्राप्त करना;

(ix) उपर्युक्त (8) में प्राप्त टिप्पणियों की उपयोगिता के आधार पर जांच करें , उन्हें एकत्रित करें और मासिक समीक्षा बैठकों में प्रस्तुत करें। यदि कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो उसे मासिक समीक्षा बैठकों के दौरान रिपोर्ट किया जा सकता है;

(x) भारत की ओर से एक व्यापक प्रतिक्रिया तैयार करें जिसमें प्रस्तावित उपाय के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक/प्रथाएं आदि शामिल हों , जिन्हें सदस्य के समक्ष उठाया जाना चाहिए तथा मसौदा उपाय को टिप्पणी अवधि के भीतर अधिसूचित किया जाना चाहिए;

(xi) भारत द्वारा उठाए गए प्रश्न पर अधिसूचित देश की प्रतिक्रिया की जांच करना तथा भारत द्वारा उठाए जा सकने वाले अतिरिक्त मुद्दों का प्रस्ताव करना;

(xii) एसपीएस और/या टीबीटी समिति में सदस्य देश के विरुद्ध उठाए जा सकने वाले संभावित विशिष्ट व्यापार चिंताओं (एसटीसी) के लिए विवरण प्रदान करना;

(xiii) अधिसूचनाओं, भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों, अधिसूचित देश की प्रतिक्रिया और भारत द्वारा उठाए गए अनुवर्ती प्रश्नों पर जानकारी युक्त व्यापक डेटाबेस/रिकॉर्ड तैयार करना।

(xiv) अधिसूचनाओं की निगरानी पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करें और कोर समिति की बैठक के दौरान एक विस्तृत प्रस्तुति दें। प्रस्तुति में देश-वार जांच की गई अधिसूचनाओं की कुल संख्या की पहचान की जाएगी , इसमें शामिल मुद्दों और प्रभावित उत्पाद के साथ महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर कार्रवाई का सुझाव दिया जाएगा।

(xv) मौजूदा या प्रस्तावित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में एसपीएस और टीबीटी से संबंधित मुद्दों पर आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सलाह (कानूनी और गैर-कानूनी दोनों पहलुओं को शामिल करते हुए) प्रदान करें। इसमें समस्या विवरण , चिंताएं,

संभावित समाधान शामिल हो , जिसमें अन्य बातों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) डीओसी/एपीडा/ईआईसी को संक्षिप्त सारांश के साथ तिमाही और मासिक कार्य-निष्पादनरिपोर्ट/मूल्यांकन रिपोर्ट भेजें।

(xvii) कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर अपनी कोर टीम की संरचना प्रस्तुत करें, तथा कोर टीम में किसी भी बाद के परिवर्तन के बारे में डीओसी, एपीडा और ईआईसी को 15 दिनों के भीतर सूचित करें; तथा

(xviii) यूरोपीय संघ, अमेरिका आदि देशों के आगामी विनियमों पर कानूनी और गैर-कानूनी दोनों पहलुओं सहित विस्तृत विश्लेषण प्रदान करना।

(xix) डब्ल्यूटीओ, एसपीएस-टीबीटी, कार्य/गतिविधि से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक मामला जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है लेकिन असाइनमेंट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक माना जाता है, उसे कार्य-क्षेत्र के भाग के रूप में माना जाएगा।

5. पात्रता मानदंड:

(i) फर्म/एजेंसी का दिल्ली में एक स्थापित भौतिक कार्यालय होना चाहिए।

(ii) फर्म/एजेंसी के पास सरकार , निर्यातकों, आयातकों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हाउस आदि के लिए डब्ल्यूटीओ, विदेशी व्यापार , एसपीएस/टीबीटी और/या कृषि निर्यात संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

(iii) फर्म/एजेंसी के पास सरकार , निर्यातकों, आयातकों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हाउस आदि के लिए डब्ल्यूटीओ, एसपीएस-टीबीटी मामलों में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अनुभव होना चाहिए;

(iv) साझेदारी/टाई-अप/संयुक्त उद्यम की अनुमति नहीं है।

(v) फर्म/एजेंसी की पिछले 3 वर्षों के दौरान व्यावसायिक सेवाओं से वार्षिक आय कम से कम 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये मात्र) होनी चाहिए।

(vi) टीम लीडर और वरिष्ठ सहयोगियों को सरकार, उद्योग और हितधारकों आदि के साथ कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए जो एसपीएस और टीबीटी मुद्दों से जुड़े हों।

(vii) कम से कम पांच सदस्यों की एक **समर्पित कोर टीम** होनी चाहिए जो एसपीएस और टीबीटी मुद्दों पर कार्य करेगी और प्रत्येक सदस्य के पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए (टीम लीडर और वरिष्ठ सहयोगियों के पास एसपीएस और टीबीटी मुद्दों में शामिल सरकार, उद्योग और हितधारकों आदि के साथ काम करने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए।) समर्पित टीम में कानूनी पृष्ठभूमि वाले कम से कम दो सदस्य होने चाहिए , कम से कम एक एसपीएस और टीबीटी समझौतों की तकनीकी पृष्ठभूमि वाला और एक व्यापार विश्लेषक होना चाहिए।

(viii) फर्म/एजेंसी को टीम लीडर और कोर टीम के सदस्यों का बायोडाटा प्रस्तुत करना होगा।

(ix) कोर टीम के पास कार्य-क्षेत्र को निष्पादित करने की क्षमता होनी चाहिए।

(x) कोई भी फर्म/एजेंसी जिसे भारत सरकार/किसी राज्य सरकार/सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्ट किया गया हो, पात्र नहीं होगी। उक्त का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. नियुक्ति की अवधि

सौंपा गया कार्य प्रारंभ में एक (**1**) वर्ष के लिए वैध होगा , और बाद में समय-समय पर मूल्यांकन किए गए संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा, हालांकि, कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक नहीं।

7. अनुबंध की समाप्ति

1) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

2) अनुबंध को एपीडा/ईआईसी द्वारा समाप्त किया जा सकता है:

क) यदि फर्म/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत कार्य, कार्य-क्षेत्र के अनुसार नहीं है,

ख) यदि फर्म/एजेंसी अनुचित देरी से रिपोर्ट प्रस्तुत करती है;

ग) यदि किया गया कार्य एपीडा/ईआईसी के अनुसार संतोषजनक नहीं है; और

घ) यदि फर्म/एजेंसी कार्य-क्षेत्र के अनुसार कर्तव्य पूरा करने से इनकार करती है।

8. नियम और शर्तें

(1) फर्म/एजेंसी की यह एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियाँ कार्य-क्षेत्र और सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हों। फर्म/एजेंसी अपने दायित्वों को पूरी तत्परता , दक्षता के साथ आम तौर पर स्वीकृत पेशेवर तकनीकों और प्रथाओं के अनुसार पूरा करेगी और ठोस प्रबंधन प्रथाओं का पालन करेगी।

(2) कोर टीम- फर्म/एजेंसी को टीम लीडर की देखरेख में डब्ल्यूटीओ, विदेशी व्यापार और कृषि निर्यात के क्षेत्र में सक्षम एक कोर टीम का गठन करना होगा। टीम लीडर/वरिष्ठ सहयोगी डिलीवरेबल्स का गुणवत्तापूर्ण आउटपुट सुनिश्चित करेंगे। फर्म/एजेंसी की कोर टीम की संरचना कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर डीओसी, एपीडा और ईआईसी को सूचित की जानी चाहिए। कोर टीम में किसी भी बाद के बदलाव के बारे में ऐसे किसी भी बदलाव के 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।

(3) डिलिवरेबल्स की आवधिक समीक्षा - डीओसी/एपीडा/ईआईसी समय-समय पर प्रदर्शन/डिलीवरेबल्स की समीक्षा करेंगे। डीओसी/एपीडा/ईआईसी द्वारा समय-समय पर फर्म/एजेंसी को दी गई टिप्पणियों को डिलीवरेबल्स में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

(4) गोपनीयता: फर्म/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके विशेषज्ञ और कार्य के लिए नियुक्त कार्मिक, इस कार्य की अवधि के दौरान , कार्य से संबंधित किसी भी स्वामित्व या गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे।

(5) हितों का टकराव : फर्म/एजेंसी को इस आशय का वचन देना होगा कि न तो एजेंसी और न ही उनके बाहरी विशेषज्ञ और न ही असाइनमेंट में जुड़े कार्मिक , इस कार्य की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यवसाय या पेशेवर

गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे , जो इस असाइनमेंट के तहत उन्हें सौंपी गई गतिविधियों के साथ संघर्ष करती हों।

(6) वरिष्ठ विशेषज्ञों और कोर टीम की उपलब्धता : फर्म/एजेंसी को जब भी आवश्यक हो , तत्काल मामलों के निपटान के लिए , मंत्रिस्तरीय बैठकों में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित होने, अल्प सूचना पर इनपुट प्रदान करने आदि के लिए अपने प्रमुख और वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ-साथ कोर टीम की उपलब्धता के बारे में एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

(7) फर्म/एजेंसी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज डीओसी/एपीडा/ईआईसी की संपत्ति होंगे:

इस असाइनमेंट के अनुसरण में फर्म/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत परामर्श पत्र/रिपोर्ट , अन्य दस्तावेज डीओसी/एपीडा/ईआईसी की संपत्ति बन जाएंगे और बने रहेंगे , तथा फर्म/एजेंसी, इस कार्य की समाप्ति तक या समाप्ति से पहले, ऐसे सभी दस्तावेजों को डीओसी/एपीडा/ईआईसी को सौंप देगी , साथ ही उनकी विस्तृत सूची भी सौंपेगी। विकसित, अनुरक्षित और होस्ट किया गया संपूर्ण डाटाबेस और एप्लिकेशन डीओसी/एपीडा/ईआईसी की परिसंपत्तियां होंगी और अनुबंध की समाप्ति/समाप्ति पर डीओसी/एपीडा/ईआईसी को सौंप दी जाएंगी।

(8) डेटाबेस तक पहुंच डीओसी, एपीडा और ईआईसी को हर समय उपलब्ध कराई जाएगी: इस अनुबंध के कार्यान्वयन के लिए वाणिज्य विभाग , एपीडा और ईआईसी की एक संयुक्त समिति होगी।

(9) संयुक्त समिति निम्नलिखित का अधिकार सुरक्षित रखती है:

(i) संयुक्त समिति की राय में , यदि डिलिवरेबल्स अपेक्षित आउटपुट के अनुरूप नहीं हैं, तो चयनित पक्ष के साथ अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) इस संबंध में संयुक्त समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। संयुक्त समिति उपरोक्त कार्रवाई से होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(iii) यदि संयुक्त समिति की राय में ऐसा करना जनहित में या असाइनमेंट के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन है , अनुबंध की शर्तों और नियमों में संशोधन करना। इस संबंध में संयुक्त समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(iv)इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए , संयुक्त समिति का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

9. विवाचन:

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि समझौते के तहत उत्पन्न कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद (उन मामलों को छोड़कर , जिनका निर्णय इस समझौते के तहत विशेष रूप से प्रदान किया गया है) अनसुलझा रहता है , तो उसे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा और दिया गया निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान एपीडा/ईआईसी का कार्यालय या संयुक्त समिति द्वारा तय किया गया कोई अन्य स्थान होगा।

10. भुगतान की शर्तें:

भुगतान तिमाही आधार पर जारी किया जाएगा।

11. कार्य-निष्पादकता आश्वासन:

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य–क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

12. बयाना जमा-राशि (ईएमडी): फर्म/एजेंसी को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की ईएमडी जमा करनी होगी। ईएमडी को नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में तैयार किया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को ईएमडी चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से होना चाहिए।

13. चयन प्रक्रिया:

(1) चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व बैठक , प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन , चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा दस्तावेजों और प्रस्तुतिकरण के अंकों के आधार पर बोलीदाताओं की अंक-सूची तैयार करने के लिए वित्तीय बोलियों को खोलना शामिल है।

(2) बोली-पूर्व बैठक **11 सितंबर 2024 को दोपहर 12 बजे एपीडा, नई दिल्ली** में आयोजित की जाएगी और बोली -पूर्व बैठक का कार्यवृत्त एपीडा की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने के लिए बोली -पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिक्षा करें।

(3) **बोलियों का मूल्यांकन**:

(i) एपीडा की एक समिति प्राप्त दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली बोलीदाता एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

(ii) बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा – पहला, तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली खोलना।

(iii) बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए, एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

(iv) प्रस्तुतिकरण में दृष्टिकोण , कार्यप्रणाली, कार्य योजना और टीम संरचना और विस्तृत बायोडाटा के लिए अंक दिए जाएंगे। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**अधिकतम अंक**
(i)	अधिसूचनाओं को अग्रेषित करने की कार्यप्रणाली, उनका वर्गीकरण, सार और संक्षिप्त विवरण तैयार करना , डीओसी द्वारा निगरानी के लिए साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना , आपातकालीन	**40**

<table>
<tr><td></td><td>अधिसूचनाओं पर प्रकाश डालना , साप्ताहिक बैठकों के दौरान टिप्पणियों और उनकी प्रस्तुति की जांच करना , भारत से आधिकारिक प्रतिक्रिया तैयार करना और उस पर आगे की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना, विशिष्ट व्यापार सरोकार , अधिसूचनाओं की निगरानी और उनकी प्रस्तुति के लिए एसओपी, परामर्श कार्य,</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>फर्म में कानूनी सलाहकारों की संख्या और उनका अनुभव (उनका नाम और विशेषज्ञता का क्षेत्र इंगित करें)
(a) 5 वर्ष से 10 वर्ष .....5 अंक
(b) 10 वर्ष व अधिक.....10 अंक</td><td>10</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>कोर टीम की संरचना
(क) सदस्यों की सं.
(ख) टीम लीडर का नाम, विशेषज्ञता और अनुभव
(ग) वरिष्ठ एसोसिएट्स/एसोसिएट्स का नाम, विशेषज्ञता और अनुभव</td><td>10</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्म द्वारा अर्जित वार्षिक व्यावसायिक शुल्क। यह आय केवल आवेदक फर्म के नाम पर होगी , न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर, भले ही वे कानूनी व्यावसायिक में हों। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:<table><tr><td>क. 50.00 लाख रु. से 1.00 करोड़ रु. प्रतिवर्ष</td><td>3 अंक</td></tr><tr><td>ख. प्रतिवर्ष 1.00 करोड़ रु. से अधिक</td><td>5 अंक</td></tr></table></td><td>5</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>विदेशी व्यापार से संबंधित कानूनी मामलों पर सलाह देने का अनुभव। अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:<table><tr><td>क. 3 से 5 वर्ष</td><td>3 अंक</td></tr><tr><td>ख. 5 वर्ष से अधिक</td><td>5 अंक</td></tr></table></td><td>5</td></tr>
</table>

(v) सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी।

(vi) चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति पर किया जाएगा। क्यूसीबीएस पद्धति के तहत वित्तीय बोलियों पर अंकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा:

एल1 = 30 अंक
एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

(vii) वित्तीय बोलियों पर अंकों की गणना के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोलियों के अंकों को जोड़ा जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

(viii) चयन समिति अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर कोई दायित्व डाले बिना किसी भी समय घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएँ जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

14. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली फर्म/एजेंसी को निम्नानुसार दो अलग-अलग लिफाफों में बोली प्रस्तुत करनी होगी:

कवर 'क' –तकनीकी बोली: इसमें निम्न शामिल होगा:

(i) दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली, कार्य योजना , टीम संरचना और टीम लीडर और सहयोगियों के विस्तृत बायोडाटा को निर्दिष्ट करते हुए पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक-1

(ii) अनुलग्नक-3: पिछले 3 वर्षों यानी 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए यूडीआईएन के साथ अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वार्षिक आय का प्रमाण पत्र (केवल शुल्क)।

(iii) फर्म के निगमन/पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति

(iv) सहायक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई प्रासंगिक सेवाओं की सूची।

(v) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।

(vi) पैन कार्ड की प्रति

(vii) अनुलग्नक-4: ब्लैक लिस्ट में न होने की घोषणा

कवर 'ख' – वित्तीय बोली (अनुलग्नक -2)

15. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: इन दो मुहरबंद लिफाफों ('क' और 'ख') को एक बाहरी मुहरबंद लिफाफे (कवर) में रखा जाएगा , जिसके ऊपर **'डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों से एसपीएस और टीबीटी अधिसूचनाओं को संभालने में एपीडा और ईआईसी की सुगमता के लिए फर्मों / एजेंसियों (अधिमानतः कानूनी फर्मों) से बोलियां** ' लिखा होगा और इसे महाप्रबंधक (डब्ल्यूटीओ) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 को **24 सितंबर 2024 को 1700 बजे तक** पहुंच जाना चाहिए।

Annexure I

APPLICATION FORM

S.No.	Particulars	Details	
1.	Nameofthe Law Firm/Agency		
2.	Address,emailandphonenumber		
3.	Name and Designation of the Authorized Signatory with email and mobile no.		
4.	Approach&Methodologytobeadoptedforthe scope of work and deliverables (Please attach a separate sheet- Annexure-A)		
5.	List of relevant services rendered during the last three financial years along with work order and completion certificate Please attach a separate sheet- Annexure-B)		
6.	FinancialincomeoftheFirm/Agency,during last3financialyears2021-22, 2022-23and 2023-24	Year	Income
		2021-22	
		2022-23	
		2023-24	
7.	Experienceofthe firm/agencyinundertakingthe task of WTO for SPS- TBT issues, Foreign trade and Agri exports (Please attach a separate sheet- Annexure-C)		
8.	Composition of Core Team including Team Leader/ Senior Associate		
9.	Experience of the team leader along with CVs of the team members (Please attach a separate sheet- Annexure-D)		
10.	CopiesofGSTregistration,PANcard,Firm incorporation/Registration certificate etc.		
11.	DetailsofEMDofRs.1,00,000/-(RupeesOne Lakh Only) in the form of Demand Draft		

Date :

(SignatureoftheAuthorized Signatory)

Seal of the Firm

Annexure-2

'Bids from Firms/ Agencies (preferably Law Firms) to facilitate APEDA and EIC in handling SPSandTBT notifications from WTO member countries'

FINANCIAL BID

Note: The Firm is requested to quote quarterly fee (inclusive of GST) for the work assigned.

Sr. No.	**Activity**	**Amount in Rs.**
1	Professional Fee for the Scope of Work mentioned in the bid document	
2	**Amount of Applicable taxes**	
3	**Total Amount (with taxes)**	

Total Amount in words: Rupees ….

Signature of Authorised Signatory

Seal of the firm

Date:

Place:

Annexure-3

'Bids from Firms/ Agencies (preferably Law Firms) to facilitate APEDA and EIC in handling SPSandTBT notifications from WTO member countries'

Proforma for CA Certificate

I /We, Proprietor / Partner / Director of _____ (Name of CA Firm) do hereby confirm that M/s._____ (Bidder), a Proprietorship / Partnership / Company having its registered office at _____, having PAN No. _____ and GST No. _____ which is valid from_____ (copy attached) and hereby declare and affirm as under:

1. That the Law Firm is in existence in the present status from.....(date).

2. That the details of annual income from professional fee for Foreign Trade and agri-exports, WTO issues are as follows:

S. No.	**Financial Year**	Annual Income from professional fee **(in Rs.)**
1	2021-22	
2	2022-23	
3	2023-24	

3. That the above work was obtained in the entity's own name and the billing /payment was collected in the entity's own bank account.

Declaration

I have independently verified the above-mentioned details with books of accounts, 26AS statements, and GST Returns and found them to be true and correct

Counter-signed:

Signature of Authorized Signatory
Name of Authorised Signatory
Partner/Proprietor / Director

Seal of the Firm

Signature:

Name and designation
Seal of CA firm
UDIN

Date:
Place:

ANNEXURE-4
(To be provided on the Letter Head of the Firm)

'Bids from Firms/ Agencies (preferably Law Firms) to facilitate APEDA and EIC in handling SPSandTBT notifications from WTO member countries'

To
The General Manager (WTO),
APEDA,
New Delhi-110016

Subject: Declaration for not being Black-Listed

Sir,

With reference to the bid on the subject cited above, I, …… (Name and designation of the Signatory) hereby declare and confirm that M/s. … (Name of the Agency) has not been black-listed or declared as ineligible by the Central Government/ State Government / Public Sector Undertaking from participating in future bids due to unsatisfactory performance, corrupt, fraudulent or any unethical business practices or any other reasons, as on the date of submission of the bid.

Signature of Authorised Signatory

(Name of Authorized Signatory)
Designation with seal:

Date:
Place:

****